Inflow of Private Investment in basic and Cellular Telephone Services

*196. DR. MANMOHAN SINGH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the inflow of private investment in basic and cellular telephone services since 1995-96;

(b) the factors which are preventing a larger inflow into these sectors; and

(c) what steps are contemplated to resolve the issues that have arisen?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI JAGMOHAN): (a) According to the information made availabale by the Industry, the total private investment in basic services from 1995-96 was Rs. 1339 crores upto July, 1998 and in cellular services was Rs. 7863.25 crores upto February, 1998.

(b) and (c) Inflow of private investments depends upon demand for basic and cellular telephones in the market and the way the business is conducted by the Companies (28) who have obtained licences (48) and entered into licence agreeement with the Government. A Group on Telecommunications has been constituted with a view to formulating proposals for formulation of new Telecom Policy. The Government would take appropriate decisions as and when the proposals of the said Group are received.

डाक एवं तार पूल के आवासों का सामान्य पूल के आवासों में विलय

*197 **श्री मुनव्वर हसन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)दिल्ली में अनेक मंत्रालय के अधीन डाक विभाग, उत्तरी दूर-संचार विभाग व महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की उन कालोनियों की संख्या और ब्यौरा क्या हैं जिनमें संचार मंत्रालय के कर्मियों को मकान आबंटित किए गए हैं;

(ख)क्या यह सच है कि संचार मंत्रालय में कार्यरत कर्मियो को शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के सम्पदा निदेशालय द्वारा आवास आबंटित किया जाना चाहिए; और

(ग)यदि हां, तासे सरकार संचार मंत्रालय में कार्यरत कर्मियों के पूल में रखे गए आवासों का सम्पदा निदेशालय के आवासीय पूल में कब तक स्थानांतरित कर देगी?

संचार मंत्री (**श्री जगमोहन**) :

डाक विभाग	दूर संचार विभाग
(क) डाक विभाग की ऐसी कालोनियों की संख्या और उनका ब्यौरा निम्ननुसार हैं, जिनमें संचार आबंटित किए गए है:	(क) उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र : विवरण निम्ननुसासर हैं: 1. पंखा रोड, जनकपुरी 2.पंखा रोड, जनकपुरी 3. अतुल ग्रोव रोड 4. सेवा नगर 5. कश्मीरी गेट
कालोनियों के नाम	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड: जिन कालोनियों का रख-रखाव महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता हैं, उनमें ऐसे आबंटन नहीं किए गए हैं।
1. रामकृष्णपुरम	
2. कालीबाड़ी	
3.सेवा नगर	
4.सरोजनी नगर	
5.मोती बाग	
6.पंखा रोड	
7.अतुल ग्रोव रोड	
8. जनकपुरी	

(ख) डाक विभाग	(ख) दूरसंचार विभाग
यह सही है कि संचार मंत्रालय (मुख्यालय) में कार्यरत कर्मचारियों को संपदा निदेशालय द्वारा मकान आबंटित किए गए जाने चाहिए।	जी हां।
(ग) डाक विभाग	(ग) दूरसंचार विभाग
डाक आवास पूल को सम्पदा निदेशालय सामान्य पूल में आतंरित/विलयित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। तथापि, डाक विभाग (मुख्यालय) के ऐसे कर्मचारियों को, जिनके पास डाक आवास पूल का मकान हैं, जहां कहीं भी उन्हें पहले सलाह नहीं दी गई, यह सलाह दी जाएगी कि वे सम्पदा निदेशालय के सामान्य पूल से आवास लेने के लिए आवेदन करें।	उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पूल कां संपदा निदेशालय के सामान्य पूल में अंतरित /विलयित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं, तथापि, संचार मंत्रालय (मुख्यालय) के ऐसे कर्मचारियों को, जिनके पास उत्तरी दरसंचार क्ष्ज्ञेत्र पूल का मकान हैं, जहां कहीं भी उन्हें पहलें सलाह नहीं दी गई हैं, यह सलाह दी जाएगी कि वे संपदा निदेशालय के सामान्य पूल से आवास लेने के लिए आवेदन करें।

Development of Heritage tourism

*198.SHRI LAJPAT RAI: will the minsiter of TOURISM be pleased tos tate:

(a) whether ther is any proposal for development of heriutage tourism in the country particularly in the States of punjab, maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat during the Ninth five year Plan as well as in the current financial year;

(b) if so, since when the said scheme is in operation;

(c) the facilities being provided by the said State Governments for converting the mansions forts and palaces into hotels under the said scheme and the maximum limit of facilities/assistance likjely to be provided; and

(d) the extent of financial assistance provided to the owners of the said heritage hotels?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF TOURISM (SHRI OMAK APANG): (A) yes, Sir. The Minsitry of Tourism is actively encouraging "herritage tourism in the country. A scheme for classification of hertitage hotels has been introduced by the Ministry of Tourism, Govt. of India. it covers the States of Punjab, Maharashtra, Madhya pradesh and Gujarat also.

(b) The Heritage Hotels classification guidelines have been in operation since 1996.

(c) No specific additional facilities are provided by the State Government except for the State of Gujarat which provides 100% tax relief for the taxes like entertainment tax, luxury tax and telectricity duty as well as revolving fund for 50% of margin money by way of loan at half the rate of interest:

(d) On the recommendation of the Ministry of Tourism, Govt, of India the promoters are availing financial assistance from the Tourism Finance Corporation of India, State Financial Corporations and the State Industrial Development Corporations. The Government of India also extends fiscal concessions like income tax benefits, interest subsidy, etc.